

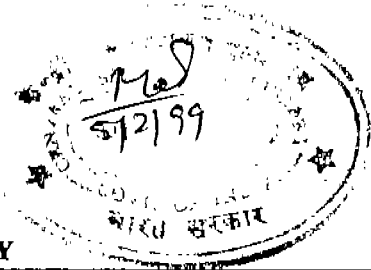


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 237]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 1998/आश्विन 29, 1920

No. 237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1998/ASVINA 29, 1920

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1998

एफयू-32/97-आईपीसी-1.— 1. तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र

1.1 भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1991 में आरंभ की गई निम्नी विद्युत नीति की अनुपालना में तथा संभाव्य अत्यंत गम्भीर विद्युत के संकट को देखते हुए त्वरित क्षमता अभिवृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 6-11-1995 के संकल्प सं. ए-27/94-आईपीसी (खण्ड-2) के द्वारा निजी क्षेत्र यूनितों को आदान-प्रदान किए जा सकने वाली (रेसिप्रोकेटिंग) डीजल ईंधन उत्पादन (डीजी) यूनितों को लगाए जाने तथा मुख्य ईंधन तेलों जैसे हैवी पेट्रोलियम स्टॉक (एचपीएस), लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस), हैवी फर्नेश ऑयल (एचएफओ) और प्राकृतिक गैस, जब कभी भी उपलब्ध हो, प्रयोग करने की अनुमति देने के निर्णय की घोषणा की थी। तदुपरान्त, दिनांक 14 मई, 1996 के संकल्प संख्या सी-355/95-आईपीसी-1 के द्वारा निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य ईंधन के रूप में पेट्रोलियम—कोक और बैक्जूम रेसिड्यू के प्रयोग की भी अनुमति प्रदान कर दी गई। सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए तरल ईंधनों के प्रयोग संबंधी नीति की समीक्षा की है तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

- (i) विद्युत उत्पादन के लिए सभी गैर-परंपरागत ईंधन जैसे कि कंडेसेंट तथा ओरी-मल्लन के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) विद्युत उत्पादन के लिए एचएसडी की अनुमति केवल अगम्य और दुर्लभ स्थानों के मामले में प्रदान की जाएगी, जहां लघु डीजल आधारित क्षमताओं को स्थापित किया जाना है तथा जहां अन्य ईंधनों का प्रयोग व्यवहार्य नहीं है।
- (iii) मुख्य ईंधन के रूप में फर्नेश ऑयल का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथापि पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान लिंकेजों के बाहर नये फर्नेश ऑयल आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए एकीकृत गैसीकरण संयुक्त साइकिल (आईजीसीसी) प्रौद्योगिकी अथवा किसी अन्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा जिससे सल्फर की मात्रा को स्वीकार्य सीमा तक लाया जा सके, यदि फर्नेश ऑयल में सल्फर की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक हो।

2. प्रचालन के मानदण्ड

कन्डेसेंट, ओरीमल्लन और एचएसडी पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए प्रचालन तथा संयंत्र भार अनुपात आदि के मानदण्ड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43-ए की उपधारा (2) के तहत इनके संबंध में संशोधनों के अध्याधीन, यदि कोई हो, निर्धारित किए जायेंगे।

3. शर्तें एवं निबन्धन

3.1 संकल्प सं. ए-27/94-आईपीसी (खंड-2), दिनांक 6 नवम्बर, 1995 में परिकल्पित सभी शर्तें एवं निबन्धन मुख्य ईंधन के रूप में कन्डेसेंट, ओरीमलशन और एचएसडी आधारित विद्युत उत्पादक संयंत्रों के मामले में लागू होंगे। तथापि, नई परियोजनाओं के लिए के.वि.प्रा. की सिद्धांत रूप में स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

वी. के. पंडित, सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 15th October, 1998

FU-32/97-IPC.L—1. Liquid fuel based power plants.

1.1 In pursuance of the private policy launched by the Government of India in October, 1991 and with a view to ensuring a quick capacity addition in the background of a likely severe power crisis, the Government had announced vide Resolution No. A-27/94-IPC(Vol. II) dated 6-11-1995 the decision to permit private sector units to set up diesel engine generating (DG) units of reciprocating type and using heavy fuel oils such as Heavy Petroleum Stock (HPS), Low Sulphur Heavy Stock (LSHS), Heavy Furnace Oil (HFO) and Natural Gas, wherever available, as primary fuel. Subsequently, vide Resolution No. C-355/95-IPC.1 dated 14th May, 1996, the use of petroleum coke and vacuum residue as primary fuel for power generation in the private sector was also permitted. The Government has reviewed the policy on use of liquid fuels for power generation and the following decisions have been taken :

- (i) All non-traditional fuels, such as condensate and orimulsion would be permitted for power generation.
- (ii) HSD would be permitted for power generation only as a special case in inaccessible and isolated areas where small diesel based capacities are sought to be set up and where use of other fuels is not feasible.
- (iii) FO has already been allowed for use as primary fuel. However, taking into account the environmental implications, it will be mandatory for new FO based power plants beyond the existing linkages to use Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) technology, or any other technology that would bring sulphur content to within acceptable limits, if the F.O. contains sulphur beyond permissible limits.

2. Norms of Operation :

The norms of operation and Plant Load Factor (PLF) etc. for power plants based on condensate, orimulsion and HSD would be as laid down by the Central Electricity Authority (CEA), subject to modifications thereof, if any, under Sub-section (2) of Section 43A of the Indian Electricity (Supply) Act, 1948.

3. Terms and conditions :

3.1 All the other terms and conditions envisaged in Resolution No. A-27/94-IPC(Vol. II) dated 6th November, 1995 will apply in the case of power generating plants based on condensate, orimulsion and HSD as primary fuels. However, there would be no requirement of 'in-principle' clearance of CEA for new projects.

V. K. PANDIT, Secy.